आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

सोमवार 18.08.2025

समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, विधानसभा के मॉनसून सत्र में लाया जाएगा विधेयक।
- महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा– उत्तराखंड, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अग्रसर।
- उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी।

कैबिनेट

प्रदेश में पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अधिनियम संशोधन विधेयक पेश होगा। अब मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को इसी प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और अरबी–फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को जुलाई 2026 से निरस्त कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता में विवाह पंजीकरण की अवधि छह माह से बढ़ाकर एक वर्ष करने का निर्णय भी लिया। इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल के पद पर अब अपर सचिव स्तर का अधिकारी नियुक्त होगा और एक्ट में सी.आर.पी.सी के साथ बी.एन.एस.एस को भी जोड़ा जाएगा। बैठक में उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम, 2020 को निरस्त करने का निर्णय भी लिया गया। इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 398 के प्रावधान लागू होंगे।

कैबिनेट ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली सुविधाओं को कानूनी रूप देने का फैसला भी किया। अब इन्हें शासनादेश की बजाय कानून के तहत परिवहन सुविधा, सम्मान राशि और 20 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।

कैबिनेट निर्णय स्वागत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक को विधानसभा में लाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। श्री भट्ट ने बताया कि अब राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मान्यता मिलेगी और सरकार इनके संचालन पर निगरानी रख सकेगी। उन्होंने कहा कि संस्थानों को मान्यता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण, भूमि, बैंक खाते और संपत्तियां संस्थान के नाम पर होना जरूरी होगा। इससे वित्तीय गड़बड़ियों और पारदर्शिता की कमी को रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए यह अधिनियम मील का पत्थर साबित होगा।

उपराष्ट्रपति चुनाव–एनडीए उम्मीदवार

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन– एनडीए के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कल नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना है जिससे कि उपराष्ट्रपति चुनाव आम सहमति से संपन्न हो जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह एनडीए के सहयोगियों दलों और विपक्ष से इस बारे में संपर्क किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बोर्ड के अन्य सदस्य इस बैठक में शामिल हुए।

चुनाव अगले महीने की 9 तारीख को होगा। जगदीप धनखड़ के उप–राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के कारण यह चुनाव कराना पड रहा है।

आवाजाही

रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से मद्महेश्वर पैदल मार्ग बणतोली के पास 40 मीटर ध्वस्त हो गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। इस दौरान फंसे 153 यात्रियों को एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन दल ने रस्सियों के सहारे सुरक्षित रेस्क्यू कर गौंडार गांव पहुंचाया।

विधायक आशा नौटियाल ने लोक निर्माण विभाग को तीन दिन के भीतर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मोरकुंड़ा नदी पर 90 मीटर लंबे झूला पुल के निर्माण को शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। वर्ष 2023 में यहां बना स्टील गार्डर पुल अतिवृष्टि में ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद से यात्रा अस्थायी व्यवस्थाओं के सहारे संचालित हो रही हैं।

## युवा संवाद कार्यक्रम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। देहरादून में एक निजी चैनल की ओर से आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आपदा के समय केवल कार्यालय से निर्देश देने के बजाय वे ग्राउंड जीरो पर रहकर काम करने को प्राथमिकता देते हैं। इसी उद्देश्य से अधिकारियों को भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने के निर्देश दिए गए थे।

मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता का उल्लेख करने हुए कहा इससे सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिले हैं और समाज में समानता की दिशा में बड़ा प्रयास हुआ है।

उन्होंने बताया कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है।

## राहत कार्य

उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य लगातार जारी हैं। खराब मौसम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राहत कर्मी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। राहत दल ने कल भागीरथी नदी में राफ्ट उतारकर घरेलू गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक सामग्री नदी पार पहुंचाई, जिसे बाद में प्रभावित गांवों तक भेजा गया। वहीं, धराली समेत अन्य सीमांत गांवों में खाद्यान्न वितरण भी किया गया। जिला प्रशासन ने कहा कि प्रत्येक प्रभावित परिवार तक समय पर राहत सामग्री पहुंचाना उसकी प्राथमिकता है। लगातार आपूर्ति से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिल रही है।

इधर, जिलाधिकारी ने डबरानी के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने बीआरओ और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को मार्ग बहाली का कार्य तेज करने और सभी आवश्यक संसाधनों का उपयोग करने के निर्देश दिए।

## स्वास्थ्य सुविधाएं

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बसंल ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को हर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, जिले के राजकीय अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं, जिससे वे किसी भी मामले में निजी अस्पतालों से कमतर न हों।

चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में जिला चिकित्सालय कोरोनेशन में विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई के लिए छह अतिरिक्त बेड, एक्सरे मशीन, फोटोथेरेपी उपकरण, डिफिब्रिलेटर, जनरेटर, मैनपॉवर और सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिक गार्ड की स्वीकृति दी गई। साथ ही पुरानी टीनशेड की जगह ऑटोमेटेड पार्किंग की संभावना पर रिपोर्ट मांगी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को रेफर करना पड़ता है, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि चिकित्सालय के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन मशीन, व्हीलचेयर, चिकित्सक यूनिफॉर्म, ड्रेसिंग ड्रम, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी सामग्री खरीदी जा चुकी है।

इसके अलावा गांधी शताब्दी चिकित्सालय में बन रहे राज्य के पहले आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के निर्माण की प्रगति पर भी चर्चा हुई। यह केंद्र दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग, श्रवण यंत्र, उपकरण, फिजियोथेरेपी और मनोवैज्ञानिक परामर्श जैसी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा।

वेटरन्स क्लब फुटबॉल

हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में वेटरन्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला देहरादून और नैनीताल की टीमों के बीच खेला गया। फाइनल का शुभारम्भ कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत ने फुटबॉल को किक लगाकर किया।

फाइनल में देहरादून ने नैनीताल को दो गोल से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब ओविड कमल और किशन जोशी को मिला।

इस अवसर पर आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में बना फुटबॉल ग्राउंड खिलाड़ियों को बेहतर अवसर दे रहा है और यह राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सहायक साबित होगा।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर

उत्तराखंड में लगातार बारिश से सामान्य जन जीवन के प्रभावित होने की ख़बर समाचार पत्रों की सुर्खियों में हैं। अमर उजाला लिखता है – रास्ते बंद होने से आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोग घरों में कैद, मोबाइल सेवा भी ठप। दैनिक जागरण धराली आपदा के राहत एवं बचाव कार्य को लेकर लिखता है – हेलीकॉप्टर नहीं उड़े, राफ्ट से पहुंचाई सामग्री।

कैबिनेट की बैठक को भी सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता से स्थान दिया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है – अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों पर नियंत्रण को प्राधिकरण। हिन्दुतान समाचार पत्र लिखता है– अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को मंजूरी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस खबर पर नवोदय टाइम्स का शीर्षक है– स्वास्थ्य विभाग को मिले 220 नए डॉक्टर।